सुखदेव सिंह

बनाम

गिढौर के महाराजा बहादुर

2 मई, 1951

[ सैय्यद फजल अली, मुखर्जी और चंद्रशेखर अय्यर जे.]

घाटवाली कार्यकाल-प्रकृति और घटनाएँ-गोवा-नमेंट घाटवाली और जमींदारी घाटवाली-अंतर-ज़मीनदार का उप-मृदा खनिजों का अधिकार-जिला राजपत्र-पहचान मूल्य।

हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सरकारी घाट वालियों को अन्य व्यक्तियों के जमींदारी में शामिल किया गया था, फिर भी जहां घाट वाली के वास्तविक चरित्र के बारे में कोई स्पष्ट सबूत सामने नहीं आ रहा है, यह तथ्य कि कार्यकाल एक जमींदारी के भीतर शामिल है और उस पर मूल्यांकन किए गए जामा द्वारा कवर किया गया है, उस पार्टी के पक्ष में पैमाना बदलना चाहिए जो आरोप लगाता है कि यह एक कार्यकाल है जो जमींदारी पर लंबित है।

केवल यह तथ्य कि घटवाली को कलेक्टर के अधीन दिखाया गया था, घटवाली के चरित्र को नहीं बदल सकता है, अर्थात, यदि यह एक जमींदारी घटवाली थी, तो यह केवल इसलिए सरकारी घटवाली नहीं बन सकती थी क्योंकि इसे कलेक्टर के अधीन बताया गया था।

जिला राजपत्र में एक बयान अनिवार्य रूप से निर्णायक नहीं है, लेकिन राजपत्र कुछ मूल्य का एक आधिकारिक दस्तावेज है, क्योंकि इसे अनुभवी अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रिकॉर्ड से तथ्य प्राप्त करने के बाद बहुत सावधानी के साथ संकलित किया जाता है। (घाटवाली कार्यकाल के इतिहास और घटनाओं पर चर्चा की गई)।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 29/1950

पटना में उच्च न्यायालय (मनोहर लाल और दास जे. जे.) के 10 अक्टूबर, 1945 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील 1942 की अपील संख्या 64 में 28 फरवरी, 1942 के डिक्री से उत्पन्न होती है, जो 1941 के सूट संख्या 10 में मोंघिर में अधीनस्थ न्यायालय की थी।

अमरेंद्र नाथ सिन्हा (के साथ समरेंद्र नाथ मुखर्जी) अपीलार्थियों के लिए।

लाल नारायण सिन्हा (के साथ आर. सी. प्रसाद) उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था-

फजल अली जे.-

यह एक फैसले की अपील है और और पटना में उच्च न्यायालय की डिक्री, वादी-प्रत्यर्थी द्वारा लाए गए स्वामित्व मुकदमे में मोंघिर के अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले और डिक्री की पुष्टि करती है।

वादी, गिधौर के महाराजा, जो नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों में सफल हुए हैं, मोंघिर जिले में गिधौर राज के नाम से जानी जाने वाली एक निष्पक्ष संपत्ति के मालिक हैं। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पूर्वजों के पास मूल रूप से महल डुमरी निस्फ कटौना टी. नंबर 325 के नाम से जाने जाने वाले घटवाली कार्यकाल में 4 आना का हिस्सा था, और बाद में निजी विभाजन द्वारा उन्हें 47 तोला के साथ मौज़ा डुमरी आवंटित किया गया था जो शिकायत की अनुसूची I में विस्तृत हैं। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पूर्वजों के खिलाफ एक चेत्रु राय द्वारा प्राप्त बंधक डिक्री के निष्पादन में, उनका ब्याज, जिसका संदर्भ दिया गया है, गिधौर के महाराजा द्वारा अपने एक कर्मचारी के नाम पर खरीदा गया था, और बाद वाले ने 19 अप्रैल, 1904 को संपत्ति का कब्जा ले लिया। 13 अगस्त, 1903 को प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पूर्वजों ने बिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे निष्पादन अदालत ने खारिज कर दिया था और निष्पादन अदालत के आदेश की अपील को उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रिवी द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। परिषद। आपराधिक अदालतों में कुछ विवादों के बाद, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने खुद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष का पट्टेदार होने का आरोप लगाते हुए, 1937 में जमुई के उप-मंडल अधिकारी से खनन लाइसेंस प्राप्त किया, और जिला मजिस्ट्रेट ने शांति भंग होने की आशंका जताते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यवाही शुरू की, जो प्रतिवादी प्रथम और द्वितीय पक्ष के पक्ष में और वादी के खिलाफ समाप्त हुई।

वादी का मामला यह है कि, धारा 144 के तहत कार्यवाही में आदेश से उत्साहित होकर, प्रतिवादियों ने वाद की अनुसूची II में उल्लिखित टोल में काम करना शुरू कर दिया और अभ्रक का एक बड़ा हिस्सा निकाला और इसलिए वह वर्तमान मुकदमे को दायर करने के लिए मजबूर हो गया। इस मुकदमे में, उन तथ्यों का पाठ करने के बाद, जिनका संदर्भ दिया गया है, उन्होंने पूरे महल दुरनरी के संबंध में उप-मिट्टी अधिकारों की घोषणा और शिकायत की अनुसूची II में निर्दिष्ट टोल में स्थित बंधक भूमि के कब्जे की वसूली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने वाद की अनुसूची II में उल्लिखित भूमि से अभ्रक या अन्य भूमिगत खनिजों को निकालने से प्रतिवादी प्रथम और द्वितीय पक्षों को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा और व्यापक लाभ के लिए भी प्रार्थना की। जिन आधारों पर इन राहतों का दावा किया गया था, उनका सारांश वाद के पैराग्राफ 12 में इन शब्दों में दिया गया हैः

"यह कि वादी प्रस्तुत करता है कि उसे दुरनरी निस्फ कटौना के 16 अन्नों के मालिक होने के नाते उक्त तालुकों के भीतर स्थित अभ्रक सहित सभी भूमिगत खनिजों पर एक अक्षम्य अधिकार और अधिकार मिला है। वादी आगे प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पूर्वजों के उक्त 4 अन्नास मोकरारी शेयरों में सभी अधिकार और ब्याज 1903 में नीलामी खरीद द्वारा वादी के पूर्वज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, प्रतिवादी प्रथम पक्ष को अभ्रक और अन्य भूमिगत खनिजों में कोई प्रकार का अधिकार और हित नहीं है और न ही प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष

द्वारा कथित रूप से उनके पक्ष में दिए गए पट्टों के तहत कोई कानूनी अधिकार प्राप्त किया है, वादी कानूनी रूप से अभ्रक सहित सभी भूमिगत अधिकारों के संबंध में अपने अधिकार और कब्जे की घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।"

मुकदमे को प्रतिवादी संख्या I से 11 (प्रतिवादी प्रथम पक्ष) द्वारा लड़ा गया था, लेकिन, जैसा कि परीक्षण न्यायाधीश ने बताया है, वास्तविक प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1, अपीलार्थी के पिता थे। इस प्रतिवादी का मामला यह था कि. दुमरी गाँव में चार अन्नों का ब्याज एक घटवाली कार्यकाल था जो अभियुक्तों के पूर्वजों को तालुका में पहाड़ी दर्रों की रक्षा करने के लिए मुसलमान शासकों द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में दिया गया था, और जिस अनुदान के तहत वे आयोजित किए गए थे, उसकी पुष्टि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन ब्राउन ने की थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे तर्क दिया कि खनिज और उपमृत्तिका अधिकार उसे घटवाली कार्यकाल के धारक के रूप में निहित किए गए थे, और यह कि वादी ने 1903 में अपनी नीलामी-खरीद से कोई अधिकार हासिल नहीं किया था क्योंकि सरकारी घटवाली कार्यकाल होने के कारण मुकदमे में संपत्ति अविभाज्य थी और परिणामस्वरूप नीलामी-खरीद अमान्य थी। अंत में, यह तर्क दिया गया कि यह प्रतिवादी और उसके पूर्वज अपने घटवाली अधिकार और वादी और उसके पूर्वजों के ज्ञान के दावे में मुकदमे से पहले 12 साल से अधिक समय से खानों और खनिजों पर कब्जे के अधिकारों

का प्रयोग कर रहे थे और इस प्रकार मुकदमे में खानों और खनिजों, विशेष रूप से वादी की अनुसूची II में निर्दिष्ट भूमि पर प्रतिकूल कब्जे द्वारा एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त कर लिया था।

अधीनस्थ न्यायाधीश ने अन्य बातों के अलावा यह अभिनिर्धारित करते हुए वाद का आदेश दिया कि विवादित कार्यकाल एक जमींदारी घाटवाली कार्यकाल था, कि यह अपरिहार्य नहीं था, कि वादी 1903 में इसे खरीदने के बाद से 1938 में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश तक संपत्ति के कब्जे में था, कि महल के मालिक के रूप में वादी खनिज और मिट्टी के नीचे के अधिकारों का हकदार था और यह कि बंधक-बिक्री के तहत केवल सतह का अधिकार वादी को दिया गया था। अधीनस्थ न्यायाधीश के निष्कर्षों को उच्च न्यायालय की अपील पर काफी हद तक बरकरार रखा गया था, इस संशोधन के साथ कि, अधीनस्थ न्यायाधीश के साथ सहमत होते हुए कि उपमृत्तिका अधिकार मालिक के पास बने हुए हैं, उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि भले ही प्रतिवादी संख्या 1 के पास उपमृत्तिका अधिकार थे, वे अधिकार 1903 की बंधक बिक्री पर पारित किए गए थे और इसलिए किसी भी स्थिति में वादी उपमृत्तिका का वास्तविक मालिक था। बचाव पक्ष में उठाए गए प्रतिकूल कब्जे की याचिका पर, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था कि प्रतिवादी संख्या 1 के पट्टेदारों की ओर से किसी भी खदान पर काम किया गया था और मामले में पेश किए गए अधिकतम साक्ष्य से

पता चलता है कि हाल के वर्षों के दौरान, शायद 1935 के बाद से, कब्जे के कुछ अलग-अलग कार्य हुए थे, और इसलिए याचिका को बरकरार नहीं रखा जा सका।

इस अपील में अपीलार्थी की ओर से जिन दो मुख्य बिंदुओं का आग्रह किया गया है, वे हैंः -

(1) कि न्यायालयों का यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा धारित घटवाली कार्यकाल एक जमींदारी घटवाली था न कि एक सरकारी घटवाली, कायम नहीं रखा जा सका और वास्तव में यह एक सरकारी घटवाली थी और इसलिए संपत्ति अविभाज्य थी और वादी को कोई अधिकार नहीं दिया गया था; और

(2) कि किसी भी स्थिति में, वादी के मुकदमे को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 142 और 144 के तहत सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।

पहला बिंदु हमें कठिनाई से मुक्त नहीं लगता है, और चूंकि इसका निर्धारण कई पुराने दस्तावेजों के उचित निर्माण पर निर्भर करता है, इसलिए हमने पक्षों को काफी विस्तार से सुना, इस तथ्य के बावजूद कि नीचे की अदालतों ने समवर्ती रूप से पाया है कि विचाराधीन कार्यकाल सरकारी घटवाली नहीं है। इससे पहले कि पक्षकारों के बीच विवाद के गुण-दोष पर विचार किया जाए, यह समझना आवश्यक है कि"घटवाल"का क्या अर्थ है और घटवाली कार्यकाल क्या है, और इन अभिव्यक्तियों का सही अर्थ जानने के उद्देश्य से, हमारी राय में पटना उच्च न्यायालय के रानी

सोनाबती कुमारी बनाम राजा कीर्तनानंद सिंह (') मामले के निर्णय से निम्नलिखित अंश को उद्धृत करना पर्याप्त है, जिसमें घटवाली कार्यकाल के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई हैः -

"शाब्दिक रूप से घाटवाल का अर्थ है दर्रों का पहरा देना और 'घाटवाली कार्यकाल' शब्द का उपयोग मुगलों द्वारा कम किराए पर या मुफ्त किराए पर दी गई भूमि पर पहाड़ी दर्रों की रक्षा करने और पहाड़ियों के पास के गांवों को अराजक पहाड़ी जनजातियों से बचाने के लिए किया जाता था। ये घाटवाली कार्यकाल बंगाल की पश्चिमी सीमा पर और विशेष रूप से खड़गपुर, गिधौर, बीरभूम, खड़गपुर, भागलपुर और सांताई परगना के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घाटवालों के पद अलग-अलग थे और उनके कार्यकाल की घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग थीं। कुछ मामलों में वे बड़ी संपत्तियों के मालिक थे, इनमें से कुछ संपत्तियां कमोबेश अर्ध-सैन्य उपनिवेशों की प्रकृति की थीं। ..... कुछ मामलों में घाटवालियों का निर्माण सीधे शासक शक्ति द्वारा किया जाता था, जबकि अन्य मामलों में उन्हें जमींदारों या जमींदारों द्वारा अपने जमींदार और किरायेदार की रक्षा करने और उन्हें अपनी कमान में एक छोटा बल रखने और सत्तारूढ़ शक्ति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया जाता था। कभी-कभी बड़ी घाटवाली संपदाओं के मालिकों ने भूमि को उपविभाजित किया और अन्य किरायेदारों को फिर से दे दिया, जो छोटे किराए का भुगतान करने के

अलावा कुछ अर्ध पुलिस और सैन्य सेवाएं प्रदान करने और सरकार या जमींदार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निर्दिष्ट संख्या में सशस्त्र लोगों को प्रदान करने की शर्त पर अपनी भूमि रखते थे।"

इस प्रकार एक सरकारी घटवाली एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में सत्तारूढ़ शक्ति द्वारा बनाया गया कार्यकाल है जिसे उसे घटवाली सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जबकि एक जमींदारी घटवाली एक जमींदार द्वारा उसे प्रदान की जाने वाली घटवाली सेवाओं के लिए बनाया गया कार्यकाल है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी यह स्थापित करने के लिए उत्सुक है कि किरायेदारी एक सरकारी घटवाली है, इसका कारण यह है कि एक सरकारी घटवाली को समान रूप से अविभाज्य माना गया है। दूसरी ओर, एक जमींदारी घाटवाली को जमींदार की सहमति से अलग किया जा सकता है, और जहां स्थानीय प्रथा अनुमति देती है, उसकी सहमति के बिना भी। जमींदारी घाटवालियों से संबंधित मामलों की रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के साथ जमींदार की सहमति का बहुत महत्व समाप्त हो गया है, और आम तौर पर यह माना जाता है कि जब यह पाया जाता है कि जमींदार से बिना किसी आपत्ति के अलगाव किया गया है। अलगाव की शक्ति की सीमा के बारे में, काली प्रसाद बनाम आनंद राय (1) में प्रिवी काउंसिल की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैंः

-

"जब एक बार यह स्थापित हो जाता है कि घाटवाल के पास अलगाव की शक्ति थी, जैसा कि पहले कहा गया है, तो वह शक्ति घाटवाली में उसके अधिकार और हित का एक अभिन्न हिस्सा है, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह उसके अपने जीवन के लिए अलगाव तक सीमित है और अब नहीं।

एक घटवाली कार्यकाल के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए, आमतौर पर उस अनुदान को संदर्भित करना आवश्यक है जिसके द्वारा कार्यकाल बनाया गया था। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी प्रदर्शनी सी (1) पर निर्भर करता है, जो अपीलार्थी के पूर्वजों को 1776 में दिया गया एक घटवाली सनद है और जो इस प्रकार हैः -

"आप बिहार प्रांत में शामिल मौज डुमरी घाट (अवैध) परगना गिधौर, सरकार मोंघिर के चौधरी, कानूनगो, जमींदार और मुतासद्दी को जानते हैं।

उपरोक्त मौज़ों में सभी राहदारियों में घाटवाड़ी के अनुलाभ अब कुंजी सिंह, जंगल सिंह, राघो सिंह और मनोरथ सिंह, उक्त मौज़ों के घाटवारों को दिए गए हैं, जो 1184 फसली के आरंभ से ही पुराने समय से प्रचलित थे। यह वांछित है कि वे उक्त घाटवारों को पुराने रीति-रिवाजों के अनुसार सभी राहदारी में घाटवाड़ी के अनुलाभ का आनंद लेने दें। उक्त घाटवारों का यह कर्तव्य होगा कि वे चौकी के कर्तव्यों का निर्वहन करने और दिन-रात चक्कर लगाकर अपने एलक के घाटों और चौकियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यदि उनके इलाका में हत्या, शरारत, चोरी, राजमार्ग

डकैती और अचानक रात में हमला किया जाता है, तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसे आकस्मिक समझें और जो लिखा गया है उसके अनुसार कार्य करें।

अगस्त शासनकाल के 18 वें वर्ष के 5 जिकादा की तारीख 1184 फसली के अनुरूप है।

यह सनद कैप्टन ब्राउन द्वारा प्रदान की गई थी, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जंगल तराई के नाम से जाने जाने वाले एक क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जो भागलपुर के दक्षिण में और राजारनहल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित एक विशाल अपशिष्ट और पहाड़ी देश है। इस दस्तावेज़ का अर्थ पटना उच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा फुलहाटी कुमारी बनाम माहेश्वरी प्रसाद (') में लगाया गया था, और जैसा कि उस मामले में डॉसन मिलर सी. जे. द्वारा बताया गया है, -

"यह भूमि का अनुदान नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए एक प्राधिकरण है जिनके नाम पूर्व में घाटवाड़ी या घाटवाली शुल्क या टोल के रूप में उन लोगों से एकत्र करने के लिए हैं जो सड़कों और दर्रों का उपयोग करते हैं, जिनकी रक्षा करने का जिम्मा घाटवाल ने लिया था।

जब हम इस सनद की तुलना कैप्टन ब्राउन द्वारा दिए गए अन्य घटवाली सनदों से करते हैं, जिनमें से कुछ पर रिपोर्ट किए गए मामलों में चर्चा की जाती है, तो अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। कुछ अन्य दस्तावेजों में-उदाहरण के लिए उस दस्तावेज़ में जो नारायण सिंह बनाम निरंजन (1)

में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का विषय था, और पटना उच्च न्यायालय के रानी सोनाबती कुमारी बनाम राजा कीर्तनंद सिंह (2) में अनुदान भूमि के बहुत व्यापक क्षेत्र के संबंध में था और यह इंगित करने के लिए भी शब्दों का उपयोग किया गया था कि सेवाओं को सीधे सत्तारूढ़ शक्ति को प्रदान किया जाना था। इसलिए, केवल यह तथ्य कि इस मामले में सनद कैप्टन ब्राउन द्वारा दी गई थी, कार्यकाल की प्रकृति के बारे में निर्णायक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह पुराने खिताबों की पुष्टि और पहचान करने के लिए उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का हिस्सा था। जैसा कि डॉसन मिलर सी. जे. द्वारा बताया गया था, सनद को रामगढ़ की दीवानी अदालत के समक्ष कुछ कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो दर्शाता है कि गिधौर के जमींदार द्वारा 2 व्यक्तियों को मौज़ा डुमरी में 8 अन्नों वाली किरायेदारी दी गई थी, जिनमें से एक कैप्टन ब्राउन के सनद में उल्लिखित घाटवाल था, कैप्टन ब्राउन की मंजूरी के साथ। वर्तमान मामले में, 1798 का एक दस्तावेज, जो मूल अदालत की कार्यवाही थी और जो फुलबती के मामले (3) का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष था, प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन हमारे सामने उसी कार्यवाही में अपीलीय अदालत का 18 मार्च, 1799 का एक निर्णय है। इस फैसले में कहा गया है कि घाटवालों का मामला यह था कि वे 3 पीढ़ियों से डुमरी गांव के आधे हिस्से पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन वर्ष 1187 फसली (1780 ईस्वी) में गिधौर का जमीनदार"राजस्व"या किराया बढ़ाना चाहता था, लेकिन उन्होंने बढ़े हुए किराए पर एक नया पट्टा या कबुलियत

स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, अदालत ने जमींदार को पट्टा देने का आदेश दिया, लेकिन जमींदार ने ऐसा नहीं किया और जबरन घाटवाल को बेदखल कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि जमींदार को उन्हें पट्टा देने और पुराने किराए पर कबुलियत प्राप्त करने का आदेश दिया जाए। अपीलीय अदालत, जिसमें जमींदार ने अपील की थी, ने पट्टा देने का आदेश देने वाली पहली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। यह दस्तावेज़ सबसे पहले यह दर्शाता है कि डुमरी के आधे हिस्से के संबंध में घाट वाली कार्यकाल 1789 से पहले 3 पीढ़ियों से अस्तित्व में था, यानी यह कैप्टन ब्राउन के सनद से बहुत पहले अस्तित्व में आया होगा, और दूसरा यह कि यह जमींदार के अधीन था। अन्यथा, यह आवश्यक नहीं था कि जमींदार को पट्टा देना चाहिए और घाटवाल को अपने पक्ष में एक कबुलियत निष्पादित करनी चाहिए।

हमारे सामने एक दस्तावेज (प्रदर्शनी 1) भी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी खादिम मुहम्मद अताउल्ला की एक रिपोर्ट है, जिसमें गिधौर के तत्कालीन जमींदारों द्वारा दिए गए कुछ बयान शामिल हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वे लगभग 700 वर्षों से जमींदारी के कब्जे में थे और"परगना के मिल्कियत जमींदारी, चौधरी और कानूनगोई हमेशा से उनके कब्जे में थे।"इस दस्तावेज़ से पता चलता है कि गिधौर एक प्राचीन जमींदारी था और जमींदार चौदरी और कानूनगोई के कार्यों को भी करता

था। अंतिम उल्लिखित बिंदु का कुछ महत्व है, क्योंकि कैप्टन ब्राउन के सनद को चौधरी, कानूनगो आदि को संबोधित किया गया था।

फुलवती कुमारी (') के मामले में, जिसका संदर्भ दिया गया है, पृष्ठ 168 पर बंगाल जिला राजपत्रक, खंड XVII से एक उद्धरण उद्धृत किया गया था, जो इस प्रकार हैः -

"1774 के आसपास इस क्षेत्र की कानूनविहीन स्थिति ने अंग्रेजों को इसे कैप्टन जेम्स ब्राउन के प्रभारी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने दो अपवादों के साथ घाटवाल के साथ संपदाओं को बसाया। ये दो अपवाद डुमरी और माहेसरी थे जिन्हें सीधे मालिकों के साथ सुलझा लिया गया था, कहानी यह थी कि घाटवाल कार्यकाल धारक कैप्टन ब्राउन के दृष्टिकोण पर भाग गए थे, डकैतों और ब्रिगेड्स के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत थी कि वे परिणामों के डर के बिना एक सरकारी अधिकारी का सामना नहीं कर सकते थे। हालाँकि, डुमरी के मामले में, घाटवालों को पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यकाल का समझौता किया गया था, वे लौट आए और गिधौर के राजा के अधीन अपने साथ इसे निपटाने के लिए एक सनद प्राप्त की। घाटवालों के साथ बसने वाली संपदाओं में से केवल दो या अब उनके वंशजों के पास हैं, अर्थात् तिलवा और केवल। अन्य काफिले गिधौर के महाराजा, चेत्रु राय, अकलेश्वर प्रसाद और रोहिणी के अन्य लोगों के हाथों में चले गए।"

जिला राजपत्र में बयान अनिवार्य रूप से निर्णायक नहीं है, लेकिन राजपत्र कुछ मूल्य का एक आधिकारिक दस्तावेज है, क्योंकि इसे अनुभवी अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रिकॉर्ड से तथ्य प्राप्त करने के बाद बहुत सावधानी के साथ संकलित किया जाता है। जैसा कि डॉसन मिलर सी. जे. ने फुलबाती के मामले (1) में बताया है, ऊपर उद्धृत बयान के बाद के पैन में कुछ अशुद्धियाँ हैं, लेकिन जहां तक इसके पहले भाग का संबंध है, ऐसा लगता है कि यह उन दस्तावेजों से काफी अनुमान लगाता है जिनके लिए संदर्भ दिया गया है।

अपीलार्थी के वकील ने इस तथ्य पर बहुत भरोसा किया कि डुमरी घाटवाली का उल्लेख कैप्टन ब्राउन के"इंडिया ट्रैक्ट्स"में घाटवालियों में से एक के रूप में किया गया है, जिसे जंगल तराई जिलों के कलेक्टर के अधीन रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिंदु को नीचे की किसी भी अदालत के समक्ष नहीं उठाया गया था, न ही कैप्टन ब्राउन का ग्रंथ उनके सामने रखा गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी की ओर से उठाई गई आपत्ति में काफी बल है कि उसे मामले का अध्ययन करने और इस परिषद के समक्ष प्रासंगिक सामग्री रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कैप्टन ब्राउन के बयान के साथ क्या अर्थ और मूल्य जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इस आपत्ति के अलावा, हमें सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है कि कैप्टन ब्राउन के बयान से लिया गया निष्कर्ष निम्नलिखित कारणों से पूरी तरह से उचित नहीं हैः -

1. केवल यह तथ्य कि घटवाली को कलेक्टर के अधीन दिखाया गया था, घटवाली के चरित्र को नहीं बदल सकता है, अर्थात, यदि यह एक जमींदारी घटवाली थी, तो यह केवल इसलिए सरकारी घटवाली नहीं बन सकती थी क्योंकि इसे कलेक्टर के अधीन बताया गया था।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल तराई जिलों के कलेक्टर के रूप में, कैप्टन ब्राउन का न केवल घाटवालों पर बल्कि उनके द्वारा प्रशासित क्षेत्र के भीतर के जमींदारों पर भी नियंत्रण था।

3. जंगल टेराई घाटवाल के संबंध में कैप्टन ब्राउन द्वारा की गई टिप्पणियाँ और जमींदार के साथ उनके संबंध शायद ही अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

जंगल टेराई घाटवालियों का उल्लेख करते हुए, कैप्टन ब्राउन अपनी पुस्तक में इस प्रकार कहते हैंः-

"सभी जंगल टेरी गौटवाल पहले कई राजाओं के अधीन थे, जिनके क्षेत्रों से उनके गौटवाल संबंधित थे; उन्होंने निष्ठावान आज्ञाकारिता के प्रतीक के रूप में थोड़ी सी श्रद्धांजलि दी, और बुलाए जाने पर अपने सभी अनुयायियों के साथ अपने राजाओं में भाग लेने के लिए सभी आक्रमणों (मुख्य रूप से दक्षिण से) का विरोध करने के लिए बाध्य थे, और अपनी-अपनी सीमाओं में की गई हर हिंसा और अनियमितता के लिए जिम्मेदार थे;-उनके अनुयायी अभी भी उनके साथ एक ही सामंती संबंधों से बंधे हैं,

और उनके पास सामंती सेवाओं के लिए भूमि है; अपने जागीरदारों पर इन प्रमुखों के अधिकार से अधिक निरपेक्ष कुछ भी नहीं माना जा सकता है।

फिर से, गिधौर के जमींदार के बारे में कैप्टन ब्राउन का वर्णन निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः-

"गुइडोर का राजा पहले काफी हद तक था, लेकिन बीरबूम और कॉम्गर कॉन के राजा द्वारा इससे की गई विजय, और इन युद्धों ने जिस स्वतंत्रता ने गौतवाल को यह मानने का अवसर दिया, उसने वर्तमान राजाओं गोपाल सिंह और दुरुप सिंह को एक गिरावट का पालन करने के लिए कम कर दिया है, कि वे शायद ही किसी भी राजनीतिक वजन के पर्याप्त परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।"

कुल मिलाकर, ऐसा प्रतीत होता है कि डुमरी के घाटवाल शायद ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण वे जमींदार से अलग हो गए और खुद को स्वतंत्र प्रमुखों के रूप में स्थापित कर सके।

साक्ष्य के दो अन्य आइटम हैं जो इस प्रश्न पर एक महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। सबसे पहले, अपीलार्थी का कार्यकाल स्थायी समझौते में गिधौर जमींदारी के भीतर शामिल किया गया था, और दूसरा, इसे गिधौर के जमींदार के तहत इस्तेमरारी मोकरारी कार्यकाल के रूप में अधिकारों के अभिलेख में दिखाया गया है। राजा लेलानुंड सिंह बहादुर, या बनाम बंगाल सरकार (1) के मामले में जहां सरकार ने राजस्व मूल्यांकन के उद्देश्य से खुरुकपुर के जमींदारी में घटवाली को फिर से शुरू करने का दावा किया

था, उस दावे को प्रिवी काउंसिल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, और जिन आधारों पर निर्णय लिया गया था, उनमें से एक यह था कि घटवाली भूमि जमींदारी का हिस्सा थी और जमींदार के स्थायी निपटान में शामिल थी और उस जमींदारी पर मूल्यांकन किए गए जामा द्वारा कवर की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रथम दृष्टया यह तथ्य कि कार्यकाल को जमींदार के स्थायी निपटान में शामिल किया गया था और उस समझौते के तहत घाटवाल को जमींदार को किराया देना था, यह अनुमान लगाता है कि घाटवाली किसी तरह से जमींदार से जुड़ी थी, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भूमि का स्थायी निपटान"उस किरायेदारी की प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगा जिस पर भूमि आयोजित की गई थी, और न ही यह उन सेवाओं को जो जमींदार के तहत निजी सेवाओं में सार्वजनिक थीं": [राजा नीलमोनी सिंह बनाम बकरनाथ सिंह (2) के माध्यम से]। ऐसे कई मामले हैं जो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें सरकारी घाटवाल व्यक्तियों की संपत्तियों को अन्य व्यक्तियों की जमींदारी में शामिल किया गया था, लेकिन जहां घाटवाली के वास्तविक चरित्र के बारे में कोई स्पष्ट सबूत सामने नहीं आ रहा है, यह तथ्य कि कार्यकाल एक जमींदारी के भीतर शामिल है और उस पर मूल्यांकन किए गए जामा द्वारा कवर किया गया है, उस पक्ष के पक्ष में पैमाने को बदलना चाहिए जो आरोप लगाता है कि यह एक कार्यकाल है जो जमींदारी पर निर्भर है। इस मामले में, स्थायी समझौते के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा को

अधिकारों के रिकॉर्ड में प्रविष्टि द्वारा प्रबलित किया जाता है जो दर्शाता है कि प्रश्न 1 में कार्यकाल जमींदार के तहत आयोजित किया गया था।

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील ने अपीलार्थी के स्वतंत्र अधिकार को दिखाने के लिए एन और एन-1 और जमींदार द्वारा दी गई कुछ किराए की प्राप्तियों पर भरोसा किया, लेकिन हमारी राय में, इन दस्तावेजों से उसे ज्यादा मदद नहीं मिलती है। प्रदर्शनी एन 1859 में एक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज को जारी किया गया एक नोटिस है, जिसके दस्तावेज़ पर उनके हस्ताक्षर सुपाठ्य नहीं हैं। जे. टी. ने थाना चकाई के उप-निरीक्षक की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि"सौतर (बुरे चरित्र) अपने निवास स्थानों पर हैं और कोई दंगे या गड़बड़ी नहीं हो रही है", और घाटवाली को अपने इलाखा के सौतरों की एक सूची तैयार करने और लाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष दाखिल करने का निर्देश देता है। प्रदर्शनी एन-1 एक समान सूचना है, लेकिन यह अधूरी है और इसका कोई संकेत नहीं है कि इसे किसने जारी किया। इसमें एक पुलिस उप-निरीक्षक की एक रिपोर्ट का पाठ किया गया है जिसमें कहा गया है कि फसलों की विफलता के कारण चोरी और चोरी हुई थी और सिफारिश की गई है कि इलाखा के जमींदारों को"घटनाओं की देखभाल करने और बुरे चरित्रों और शरारत करने वालों पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि घटनाओं को रोका जा सके।"ये दस्तावेज़ आवश्यक रूप से यह नहीं दर्शाते हैं कि अपीलार्थी एक सरकारी है। पुराने दिनों में इस

तरह के नोटिस जारी करना कोई असामान्य बात नहीं थी, जैसा कि प्रदर्शनी एन-1 से ही पता चलता है कि जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था, उसे घटवाल दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया था, यह दर्शाता नहीं है कि उसे सरकारी घटवाल के रूप में संबोधित किया गया था, न कि जमींदारी घाटवाल के रूप में।

सबूत की अगली वस्तु जिस पर अपीलार्थी ने भरोसा करने की कोशिश की, उसमें कुछ किराया रसीदें और सड़क उपकर रसीदें शामिल हैं, लेकिन ये भी उसकी मदद नहीं करती हैं, यह देखते हुए कि उनमें अन्य बातों के अलावा, एक बयान है कि जिस कार्यकाल के संबंध में रसीदें दी गई थीं, वह गिधौर के स्वामित्व वाले जमींदारी से संबंधित है।

साक्ष्य की यह संक्षिप्त समीक्षा यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता अधिकारों के अभिलेख और स्थायी समझौते के अभिलेख से अनुमानित उत्तर का खंडन करने के लिए स्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य नहीं दे पाया है, और वह अपने दावे को स्थापित करने में विफल रहा है कि विचाराधीन कार्यकाल सरकारी घटवाली है. संयोग से यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस मुकदमे से पहले के बंधक मुकदमे में बचाव के रूप में कोई आरोप नहीं था कि घटवाली अलग करने योग्य नहीं थी, और हालांकि निष्पादन कार्यवाही में यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अपीलकर्ता के खिलाफ पहली बार अदालत द्वारा निर्णय लिया गया था और अपील पर छोड़ दिया गया था। इन परिस्थितियों में, हम उन न्यायालयों के समवर्ती

निर्णय में बाधा डालने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जिन्होंने इस मामले को बहुत सावधानी से निपटाया है।

अब इस अपील में उठाए गए दूसरे बिंदु पर जाते हुए, हम पाते हैं कि प्रतिकूल अधिकार की याचिका पर प्रतिवादियों के खिलाफ नीचे दी गई दोनों अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इन निष्कर्षों पर पहुंचने में, नीचे दी गई अदालतों ने सबूतों पर पूरी तरह से चर्चा की है और अपने निष्कर्षों के समर्थन में ठोस कारण दिए हैं। यह न्यायालय आमतौर पर उन मामलों की फिर से जांच करने के लिए अनिच्छुक होता है जिनकी नीचे की अदालतों द्वारा पूरी तरह से जांच की गई है और जिन पर समवर्ती निष्कर्ष हैं। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी हमें कोई असाधारण परिस्थितियाँ दिखाने में विफल रहा है जो हमें ठोस और अच्छी तरह से स्थापित प्रथा से हटने के लिए प्रेरित करती हैं और इस दृष्टिकोण से नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

हालाँकि यह तर्क दिया गया था कि किसी भी स्थिति में वादी का मुकदमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 142 के तहत वर्जित है क्योंकि वादी पर यह साबित करने का अधिकार था कि वह मुकदमे के 12 वर्षों के भीतर विवादित भूमि, विशेष रूप से वाद की अनुसूची II में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर चुका था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा था। हमारी राय में, इस याचिका को नकार दिया जाना चाहिए। ट्रायल जज ने अपने फैसले में इन शब्दों में एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकालाः-

"वादी में दिए गए कब्जे और बेदखल करने की कहानी पर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस मामले में वादी के सतह के साथ-साथ मिट्टी के नीचे के कब्जे को साबित करने के लिए भारी सबूत हैं।"

ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायाधीश के निष्कर्ष को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, और हालांकि अपीलार्थी की ओर से इस अदालत में दायर मामले के बयान में कम से कम 16 कारण दिए गए हैं, यह नहीं कहा गया है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वादी विवादित भूमि या मुकदमे के 12 वर्षों के भीतर अनुसूची यू में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर रहा था। इस प्रकार इस अपील में आग्रह किए गए दोनों बिंदु विफल हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बिक्री द्वारा पूरा कार्यकाल वादी के पास चला गया है, लेकिन इस तथ्य के अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक जमींदार को उसके द्वारा बनाए गए किरायेदारों में भूमिगत अधिकारों का मालिक माना जाता है, इस बात के सबूत के अभाव में कि वह कभी उनके साथ अलग हुआ थाः [हरि नारायण सिंह बनाम श्रीराम चक रावर्थी (1) और दुर्गा प्रसाद सिंह बनाम ब्रज नाथ बोस (') देखें]। परिणाम यह है कि यह अपील विफल हो जाती है, और इसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ताः आर. आर. विश्वास।

प्रत्यर्थी का अभिकर्ताः आर. सी. प्रसाद

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक मनीष शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।